NT>
Title: Requests the Government to take steps to end the doctor's strike at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऑल इंडिया इंस्टीटयूट ऑफ मैडिकल साईंस में पिछले पन्द्रह दिनों से डाक्टरों की हड़ताल चल रही है। वहां लगभग पांच सौ औप्रेशन प्रतिदिन होते थे लेकिन केन्द्र शासन का ध्यान उस ओर नहीं गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि २४ घंटे के अंदर हड़ताल खत्म की जाए लेकिन केन्द्र सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। सरकार ने इसके लिए बख्शी कमेटी गठित की थी। बख्शी कमेटी की रिपोर्ट को आए हुए लगभग आठ महीने हो चुके हैं और इन आठ महीनों के बाद भी डाक्टरों की हड़ताल, जो पन्द्रह दिन से चल रही है, पर केन्द्र सरकार का कोई ध्यान नहीं है। देश के कोने-कोने से जो मरीज वहां आते हैं, उन्हें आज भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री अभी यहां पर नहीं हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन करें। ऐसा लगता है कि यह सरकार दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना करने पर पूरी तरह से उतारू है।

>DR. RAM CHANDRA DOME (BIRBHUM): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I thank you for giving me an opportunity to raise this issue. I fully endorse the views expressed by Shri Vora. My point of distinction here is that the main responsibility for the prevailing situation in AIIMS is on the part of the Government. It is a very sorry state of affairs that the senior faculty members of AIIMS have to come to the streets; it is shameful. It is against the interests of the people and I do not endorse that. But the main responsibility for the prevailing situation is with the Government alone. Therefore, immediately the Government should become active to fizzle out the strike in the greater interest of the suffering people. The Government should not sit idle and it should immediately come out with a statement on this issue.

>

श्री तारिक अनवर (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी श्री मोती लाल वोरा ने जिस बात की ओर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया है, मैं भी उसके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। भारत सरकार की उदासीनता दिखाई पड़ रही है कि ऑल इंडिया मैडिकल इंस्टीटयूट की हड़ताल को सोलह दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक भारत सरकार की ओर से कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। यह बात बिल्कुल सच है, सब लोग जानते हैं कि उत्तर भारत के गरीब और निर्धन मरीज उस संस्थान में बड़ी तादाद में आते हैं। आज हजारों मरीज सड़क पर हैं और कोई उनका इलाज करने वाला नहीं है।

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की ओर से कोई ऐसा कारगर कदम अभी तक नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में बहुत निराशा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से चाहूंगा कि इस बारे में डाक्टरों से बातचीत करे और कोई रास्ता, कोई समाधान निकाले।

DR. RAVI MALLU (NAGAR KURNOOL): Nobody from the Treasury benches is bothered to react. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister is reacting.

... (Interruptions)

>

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): मान्यवर सदस्यों ने एम्स की हड़ताल के कारण मरीजों को जो तकलीफ हो रही है, उसके बारे में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, वे मैं हैल्थ मिनिस्टर के पास पहुंचा दूंगा।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): जब हड़ताल समाप्त हो जाये तो सदन को भी बताइये।

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : खबर पहुंचाने तक आपका काम खत्म हो गया।

... (Interruptions)

प्रो.जोगेन्द्र कवाडे (चिमूर) : एक लड़की के साथ बलात्कार किया गया?

... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record except what Shri Lakshman Chanda Seth says.

(Interruptions) *

SHRI LAKSHMAN CHANDRA SETH (TAMLUK): Sir, in the past there used to be a train service between India and Bangladesh. ... (Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Prof. Joginder Kawade, your name is not in the list.

---

* Not Recorded.

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : यह एक गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : गम्भीर मामले का १० बजे के पहले नोटिस देना चाहिए।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : यह अभी आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी आया है तो कल आयेगा, आज नहीं। अभी इसके पूरा होने के बाद आपके मामले को देखेंगे।